



क्या किसानों के पास वाकई विकल्प नहीं!

पूरे पंजाब में रिलायंस की रिटेल शृंखला, निजी रोड टोल नाकों और अदाणी के भंडार केंद्र किसानों के प्रदर्शन के स्थल बने हुए हैं

साई मनीष

पंजाब के मोगा जिले के डाबरा गांव में अदाणी के गेहूं साइलो (भंडार) के बाहर अहले सुबह बुजुर्ग किसानों का एक समूह एक और दिन के विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटा था। इससे पहले रात भर उन्होंने दो लाख टन क्षमता वाले इस विशाल परिसर के बाहर प्रदर्शन किया था। पूरे पंजाब में रिलायंस द्वारा संचालित रिटेल शृंखला, निजी रोड टोल नाकों और अदाणी के अन्य साइलो इन दिनों किसानों के धरना-प्रदर्शन के स्थल बने हुए हैं। किसान हाल में बने कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

2007 में डाबरा में बने अदाणी साइलो

की तरह की केंद्र सरकार देश भर में साइलो बनाने का प्रस्ताव किया है। इसका विरोध करने वाले किसानों का कहना है कि यह आने वाले दिनों में हमारे लिए प्रतिकूल होगा। अदाणी साइलो भारत में सबसे बड़ा गेहूं भंडारण स्थल है, जिसे 2008 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सरकारी खरीद केंद्र (मंडी) के तौर पर अधिसूचित किया था। इतनी ही क्षमता का एक और गेहूं साइलो हरियाणा के कैथल में भी है। मध्य प्रदेश में भी छह जगहों पर ऐसे साइलो बने हुए हैं। नए कानून के तहत किसान मंडी जाने के बजाय अपनी उपज सीधे अदाणी के साइलो में ला सकते हैं। जहां उपज को तौला और खरीदा जाएगा। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) 30 साल के रियायती करार के तहत इस साइलो को चलाने के

लिए करोड़ों रुपये का किराया चुकाता है, वह तीन दिन में किसानों को उपज का मूल्य सीधे अदा करेगा। अदाणी के साइलो को सरकार की अधिसूचित मंडी में बदलने के पीछे तर्क दिया गया था कि मंडी में कमीशन एजेंटों को किए जाने वाले 2.5 फीसदी शुल्क की बचत होगी और किसानों को उपज की बिक्री प्रक्रिया में तेजी आएगी। नए कानून में इस तरह के सभी साइलो, गोदामों और कृषि उपज संग्रह केंद्रों को व्यापार क्षेत्र के तौर पर निर्धारित किया गया है। कोई भी किसान या कंपनी देश भर में इन क्षेत्र में कृषि उपज की खरीद-बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगी।

अदाणी के साइलो से धान के खेतों के किनारे कुछ किलोमीटर चलने के बाद दारोली भाई गांव आता है। यहां के 70

वर्षीय किसान लायब सिंह की तरह ही कई सारे किसान अपना गेहूं वर्षों से अदाणी के साइलो में जमा करते हैं। सिंह ने कहा, 'अदाणी के साइलो में गेहूं लाने का हमें काफी फायदा है। यहां मंडी की तुलना में हमारी उपज का वजन पांच से सात क्विंटल ज्यादा तौला जाता है। वे हमारे गेहूं को लेने से मना नहीं करते हैं जबकि मंडी में मामूली खामी बता गेहूं को लेने से मना कर दिया जाता है। आज मेरी उपज के दाम भी 15,000 रुपये अधिक होंगे। शुरूआती वर्षों में वे न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20 रुपये प्रति क्विंटल ज्यादा देते थे। लेकिन पिछले कुछ माल से यह लाभ नहीं दिया जा रहा है।' गांव के एक बुजुर्ग किसान गुरमेल सिंह ने कहा, 'अदाणी को मेरा गेहूं बेचने में करीब तीन घंटे का समय लगता है। मंडियों में आदतियों को गेहूं बेचने से पहले करीब तीन दिन लगते हैं। यहां वे खुद गेहूं को साफ-सुथरा और छांटते हैं। मंडियों में मेरे गेहूं की चोरी का भी जोखिम है क्योंकि यह कुछ दिनों तक खुले में पड़ा रहता है। यहां हमारी ट्रॉली उनके दरवाजे के बाहर कतार में खड़ी होती है और वे कुछ घंटे में इसे खरीद लेते हैं। लेकिन हाल में इंतजार का समय बढ़ा है और अब वे पहले की तुलना में ज्यादा गेहूं को खारिज कर रहे हैं।'

एफसीआई के मोगा बेस डिपो के एक अधिकारी ने कहा कि अदाणी के साइलो तीन स्तरों- श्रमिकों को दिहाड़ी, मंडी से गोदामों तक पहुंचाने की परिवहन लागत और गेहूं के भंडारण और परिवहन के लिए जूट की बोरी खरीदने पर सरकार के करोड़ों रुपये बचाते हैं। इन साइलो में गेहूं की बरबादी ना के बराबर है, जबकि एफसीआई के गोदामों में काफी गेहूं खराब हो जाता है।

ज्यों ही सुबह से दोपहर हुई, अदाणी साइलो के बाहर प्रदर्शन स्थल पर भीड़ जमा हो गई। अदाणी साइलो पर दिन-रात विरोध-प्रदर्शन करने वाले किसानों में से एक बूटा सिंह ने कहा, 'बड़ी कंपनियां ऐसे साइलो और गोदाम बनाएंगी और एक या दो साल आकर्षक कीमत देंगी। एक बार किसानों ने उन्हें बेचना शुरू किया और सरकार के बाजार से गायब हुई, वे जानबूझकर कीमतों को घटाना शुरू कर देंगे। क्या यह वैसा ही नहीं है, जैसा रिलायंस जियो ने किया है? मुफ्त में फोन और डेटा दो, बाजार कब्जाओ और फिर ज्यादा कीमत वसूलना

शुरू कर दो। किसान बड़ी कंपनियों के गुलाम बन जाएंगे।'

एक अन्य बुजुर्ग किसान गुरनाम सिंह ने कहा, 'नया विधेयक मंडियों को खत्म कर देगा और सरकारी खरीद चटा देगा। किसानों को एम्एसपी की गारंटी देने वाला कोई कानून नहीं है।'

सरकार ने ऐसे साइलो विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। सरकार ने आने वाले वर्षों में देश भर में एक करोड़ टन की साइलो भंडारण क्षमता विकसित करने को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 62 साइलो बनेंगे, जिनमें 10 पंजाब में बनाए जाएंगे। वहीं अन्य हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में बनेंगे। इनमें से हरके की क्षमता 50,000 टन होगी।

इस कारोबार में अदाणी के अलावा प्रेम वत्स का फेयरफैक्स समूह एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरा है। नेशनल कॉलेटरल मैनेजमेंट सर्विस (एनसीएमएस) में बहुलांश हिस्सेदारी फेयरफैक्स की है। एनसीएमएस देश भर में ऐसे साइलो बनाने के लिए कम से कम 15 ठेके मिले हैं। एनसीएमएस के ठेके के तहत देश में कम से कम आठ लाख टन क्षमता के साइलो बनाए जाने हैं। अदाणी के पास 8.75 लाख टन की साइलो भंडारण क्षमता है। वह चार लाख टन क्षमता के साइलो उत्तर प्रदेश के कन्नौज और बिहार के दरभंगा एवं समस्तीपुर में बना रही है। नए कानून से देश भर में ये साइलो और हजारों निजी गोदाम कारोबारी क्षेत्र बन गए हैं, जहां किसान अपनी उपज बेच सकते हैं और कोई भी व्यक्ति मंडी के बाहर कोई भी उपज खरीद सकता है।


कंपनी के उपाध्यक्ष पुनीत मेदीरत्ता कहते हैं, 'किसान साइलो के कुशल और पारदर्शी कामकाज से इतने खुश हैं कि उन्हें किसी भी तरह के प्रोत्साहन का लोभ देने की जरूरत नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया इतनी बेहतर है कि वे पिछले 12 साल से साइलो पर आए हैं। साइलो उनके जीवन जीने का तरीका बन गया है।'

एक बार जब कोई किसान साइलो आएगा तो उसे किसी अन्य मंडी में नहीं जाना पड़ेगा, भले ही उसे कुछ समय के लिए इंतजार क्यों न करना पड़े। अदाणी एफ लॉजिस्टिक्स इस क्षेत्र में अग्रणी है। फिलहाल हम करीब दस लाख टन खाद्यान्न का प्रबंधन कर रहे हैं। हमारी योजना है कि आने वाले वर्षों में क्षमता दोगुनी की जाए।'

कनाडा के निवेशकों को मोदी का आमंत्रण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कनाडा के निवेशकों को भारत में शिक्षा, कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत निवेशकों को राजनीतिक स्थिरता और निवेश अनुकूल नीतियों के साथ, उन सब चीजों की पेशकश करता है जो निवेशक किसी देश में निवेश करने से पहले सोचते हैं। उन्होंने इस मौके पर श्रम और कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे न केवल निवेशकों के लिए व्यापार करना सुगम होगा बल्कि किसानों तथा कामगारों को भी लाभ होगा। मोदी ने कनाडा में आयोजित इनवेस्ट इंडिया सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि एक गतिशील लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता और व्यापार अनुकूल नीतियों के साथ भारत विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य है। यह सम्मेलन भारत और कनाडा के बीच रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के मकसद से आयोजित किया गया

है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा, कृषि और श्रम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों का मकसद निजी क्षेत्र की भागीदारी में सुधार लाना है। मोदी ने कहा, 'अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी चाह रहे हैं तो वह स्थान भारत है। अगर आप विनिर्माण या सेवा क्षेत्रों में निवेश पर विचार कर रहे हैं, वह स्थान भारत है। अगर आप कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर गौर कर रहे हैं, उसके लिए भारत उपयुक्त स्थान है।' उन्होंने कहा, 'भारत की स्थिति आज सुदृढ़ है तथा कल और मजबूत होगी हम हवाईअड्डा, रेलवे, राजमार्ग, बिजली ट्रांसमिशन समेत कई क्षेत्रों में बेहतर कर रहे हैं।' मोदी ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) व्यवस्था को उदार बनाया गया है और सरकारी संपत्ति तथा पेंशन कोष के लिए कर व्यवस्था अनुकूल बनाई गई हैं। कोरोनावायरस महामारी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, 'भारत ने कोविड-19 के बीच अनूठा रुख अपनाया है। भाषा



License No. 34 of 2018, Building Plan Approved Vide Memo No. ZP-1255/JD(RD) 2019/20894 dated 30-08-2019. HARYANA RERA REG. NO. 78 OF 2019 DATED 23-12-2019


फ्लैटों का ड्रॉ

आग जनता को यह सूचित किया जाता है कि नेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अफोरेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के तहत विकसित की जा रही सनसिटी एवेन्यू 76, सेक्टर 76, जिला गुडगांव हरियाणा के फ्लैटों का ड्रॉ दिनांक 13.10.2020 को सुबह 9:30 बजे सनसिटी स्कूल (ऑडिटरियम) सनसिटी टाउनशिप, सेक्टर-54, गोलफ कोर्स रोड, गुडगांव, हरियाणा-122002 में आयोजित किया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग की मदद से YouTube लाइव पर ड्रॉ की कार्यवाही प्रसारित की जाएगी। कोविड-19 महामारी की चल रही स्थिति के कारण, कोरोना वायरस रोग के प्रसार को रोकने के लिए, सार्वजनिक सभा पर कुछ नबाल्य बात प्रतिबंध लगाया गया है। MHA/DTCP हरियाणा के विधानियों के अनुसार, ड्रॉ समिति और कर्मचारियों सहित 50 व्यक्तियों की अधिकतम शक्ति का संचालन स्थल पर किया जाएगा, शेष आवेदक YouTube लाइव के नीचे दिए गए लिंक पर ऑनलाइन करने के बाद ऑनलाइन ड्रॉ में भाग लेंगे। YouTube लिंक: <https://www.youtube.com/c/suncityprojectspltd> नोट: सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अगर वह अपना आवेदन देखना या जांचना चाहते हैं तो वह ड्रॉ से पहले (एस्टी.पी.) ऑफिस गुडगांव या डेवलपर ऑफिस में देख सकते हैं।

सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U45201DL1996PTC083915)
सनसिटी बिजनेस टॉवर, 218-224, द्वितीय तल, गोलफ कोर्स रोड, सेक्टर-54, गुडगांव-122002, हरियाणा।
Ph.: 7061700000 VISIT: www.suncityprojects.com

नए क्षेत्र में उड़ान भरने की तैयारी में शंकर

मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) के रूप में पदभार संभाला था जब उस वक्त कंपनी का



इण्डियन ओवरसीज बैंक